राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल आपराधिक याचिका संख्या 240/1990

प्रेम सिंह पुत्र सुजान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बंकिल, जिला पाली

(वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से	श्रीमती सपना वैष्णव, न्यायमित्र
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	श्री एस.के. भाटी, लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

11/11/2022

1. वर्तमान आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 374(2) के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाली द्वारा पारित 31.07.1990 के निर्णय और सजा के खिलाफ दायर की गई है। सेशन केस संख्या 18/1988 में इसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. एफ.आई.आर. में बताए गए तथ्य यह है कि 26.03.1988 को सुबह 9 बजे, चुनाराम उर्फ चुनिया (बाद में "शिकायतकर्ता" के रूप में संदर्भित) और उनके परिवार के कुछ सदस्य उनके और अपीलार्थी द्वारा सह-खेती वाले खेत में गए, और चुनिया के साथ महिलाएं आईं। सरसों के बीज (रायडा) की फसल साफ करने लगी, जिस पर

अपीलार्थी ने आपत्ति जताई। अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता और उसके साथियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और मैदान छोड़ दिया।

3. अपीलार्थी, अन्य सह-अभियुक्तों अर्थात मंग सिंह, कुन्दन सिंह, भीख सिंह, हुकम सिंह और फूटर मल के साथ, लाठियों और लोहे के पाइपों के साथ लौटे और शिकायतकर्ता और जना, कानाराम और धर्माराम नामक अन्य लोगों के साथ हिंसक हाथापाई में लगे रहे।

4. उसी दिन दोपहर 12:15 बजे शिकायतकर्ता के कहने पर रोज़नामचा (प्रदर्श पी-5) में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें देखा गया था कि अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर और उसके साथियों पर हमला करने के इरादे से हमला किया था। उन्हें मारना ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 147, 148, 149, 447 और 323 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत मामला दर्ज किया गया।

5. जांच के दौरान चूनाराम, धर्माराम, कानाराम व जाना की चोटों का पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जैसाकि भाग्य को मंजूर था, जना ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद, जना के संबंध में एक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई और तदनुसार आईपीसी की धारा 302 को मामले में जोड़ा गया।

6. 06.05.1989 को, निचली अदालतने आईपीसी की धारा 447, 148, 302, 323/149, 325 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए क्योंकि आरोपी व्यक्तियों ने "दोषी नहीं" होने का अनुरोध किया था और मुकदमे का दावा किया था: -

> *"(i) आपने 26-3-1988 को सुबह 9 बजे बनवली निवासी चुनिया कुम्हार के कब्जे में अनधिकृत आपराधिक अतिक्रमण किया और इस प्रकार, आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध किया।*

(ii) आपने अपने अन्य पांच सह-अभियुक्तों के परामर्श से उक्त तिथि को, उक्त समय पर और उक्त स्थान पर, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए घातक हथियारों से लैस एक गैरविधिक सभा की और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 का अपराध किया।

(iii) आपने घायल जना को उक्त तिथि, उक्त समय एवं बताये स्थान पर जान से मारने की नियत से लोहे के पाइप से मारकर उसके सिर में चोट पहुंचायी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा साधारण कुंद से भी मारपीट कर घायल कर दिया। जानबूझकर आपत्ति जताने पर आपने भारतीय दंड संहिता 302 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(iv) आप उक्त दिन और समय पर गैरविधिक सभा के सदस्य थे, गैरविधिक सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में हकजी, फुटरमल, कुन्दन सिंह, मांग सिंह और भीख सिंह ने धर्मा की पिटाई की और काना ने कुंद हथियारों से हमला किया जिसके कारण धर्म को साधारण चोटें आईं जबकि काना को साधारण और गंभीर चोटें आईं। गैरविधिक सभा का सदस्य होने के नाते, आप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत अपने सह-अभियुक्त के कृत्य के लिए भी जिम्मेदार हैं और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 और 323 के तहत अपराध किया है।

(v) उक्त दिन, उक्त समय और स्थान पर, आप गैरविधिक सभा के सदस्य थे, सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में, आपने अभियुक्त भीख सिंह, मांग सिंह को साधारण चोट पहुँचाने में सहायता की। चुनिया का शरीर कुंद हथियार से. आप, गैरविधिक सभा के सदस्य होने के नाते, अपने सह-अभियुक्तों के कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323 के तहत अपराध किया है।

7. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता चुनिया (पीडब्लू-1) सहित कुल 48 गवाह प्रस्तुत किए; चश्मदीद गवाह बदी (पीडब्लू-3), कक्कू (पीडब्लू-5), तीजा (पीडब्लू-6); मृतक की पत्नी, मोती (पीडब्लू-17), और डॉ. एन के शर्मा (पीडब्लू-23) जिन्होंने घायल चुनाराम, धर्माराम, कानाराम और जनाराम की चिकित्सा जांच की।

8. संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी का बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता, अन्य व्यक्तियों के साथ उस खेत में आया था, जिस पर उसने और फुटर मल ने संयुक्त रूप से खेती की थी। अपीलार्थी के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष सरसों (रायड़ा) की फसल को जबरदस्ती छीनने के लिए लाठियों के साथ आया था और उन्हें बाहर निकालने के लिए, उसने आत्मरक्षा के लिए पास में पड़े एक लोहे के पाइप को उठाया और चारों ओर घुमाया, जो शायद मृतक को लग सकता था।

9. अपीलार्थी ने यह भी कहा कि इस बीच, मांग सिंह और भीक सिंह भी पास के खेतों से उसके बचाव के लिए आए। अन्य आरोपी व्यक्तियों ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से इनकार किया।

10. अभियोजन पक्ष ने 48 गवाह (पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 48) प्रस्तुत किए जबकि अपीलार्थी ने बचाव में 5 गवाह प्रस्तुत किए। शिकायतकर्ता की ओर से, धीरेंद्र कुमार (सी. डब्ल्यू.1) गवाह बॉक्स में उपस्थित हुए। निचली अदालत ने उन सभी गवाहों की गवाही की विस्तार से जांच की और पाया कि शिकायतकर्ता पक्ष, जिसमें मृतक और अन्य घायल व्यक्ति भी शामिल थे, हमलावर थे, जो सरसों की फसल का अपना हिस्सा लेने के लिए अपीलार्थी के खेत में गए थे। निचली अदालतने, हालांकि, पाया कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई चोट फसल की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए निजी बचाव के अधिकार के तहत कवर की गई थी, हालांकि, अपीलार्थी-अभियुक्त (प्रेम सिंह) को अपराध का दोषी माना गया। आईपीसी की धारा 302 की जगह धारा 304 भाग-2 में 5 वर्ष कैद की सजा के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

11. यह मानते हुए कि अपीलार्थी को निजी बचाव का अधिकार था, निचली अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी ने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है और सामान्य विवेक वाले व्यक्ति की आवश्यकता या अपेक्षा से अधिक बल का प्रयोग किया है और इस प्रकार, उसे आईपीसी की धारा 304 के भाग- II के तहत दोषी ठहराया।

12. हालांकि, वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह ध्यान देना पर्याप्त है कि अन्य आरोपियों को गैरविधिक सभा का हिस्सा नहीं पाया गया है और जना की मौत का दोषी नहीं पाया गया है। सह-अभियुक्त मांग सिंह और भीख सिंह को काना और चुनिया को लाठी से मारने के लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी पाया गया है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी (प्रेम सिंह) को भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 148, 323/149, 325/149 और 302 के तहत दंडनीय अतिचार का दोषी नहीं पाया गया है।

14. रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मद्देनजर कि मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य सदस्यों ने अपीलार्थी के क्षेत्र से संपर्क किया है, शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि प्रेम सिंह और अन्य सह-अभियुक्तों ने अपराध करने के इरादे से उनके क्षेत्र से संपर्क किया है हत्या/घातक चोटें पहुंचाने की बात झूठी पाई गई है।

15. अपेक्षित तथ्यों के बारे में न्यायालय को अवगत कराते हुए, अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री सपना वैष्णव ने, सबसे पहले, पूर्व की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। पी-5 और तर्क दिया कि रोज़नामाचा रिपोर्ट में इस तथ्य के बारे में तनिक भी संकेत नहीं है कि अपीलार्थी-अभियुक्त प्रेम सिंह ने मृतक जना के सिर पर पाइप से वार किया था, इसलिए, निचली अदालतने ग़लती से दोषी ठहराया है अपीलार्थी ने एक ऐसी कहानी पर भरोसा किया जिसे पुलिस ने बाद में गढ़ा होगा।

16. दूसरे, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि प्रदर्श पी-43 (रिकवरी मेमो) इंगित करता है कि साढ़े 7 फीट लंबा लोहे का पाइप, कथित तौर पर मृतक को

चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार, प्रेम सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने बरामद कर लिया है, हालांकि, कोई खून नहीं है लोहे के पाइप पर दाग पाए गए इसलिए बरामद कर लिया। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालतने मृतक जना को घातक चोटें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार के रूप में लोहे के पाइप को गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि फूल सिंह (पीडब्लू-30) के बयान से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी - प्रेम सिंह पर जना, धर्म, काना, चुनिया आदि ने बिना किसी उकसावे के हमला किया था। उसकी सरसों की फसल को जबरन छीनने के लिए लाठियों और अन्य हथियारों के साथ उसके खेत में पहुंचे और इसके प्रतिशोध में, अपीलार्थी प्रेम सिंह ने खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लाठी या पाइप फेंक दिया था। उसने तर्क दिया कि अपीलार्थी की कार्रवाई निजी बचाव के उसके अधिकार के अंतर्गत थी, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता पक्ष आक्रामक था।

18. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को विस्तार से बताया कि शिकायतकर्ता पक्ष के हाथों अपनी संपत्ति और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के दौरान, अपीलार्थी ने लोहे का पाइप उठाया और उसे घुमा दिया। यदि ऐसा पाइप संयोगवश जना के सिर पर लगा और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, तो यह कोई पूर्व-निर्धारित कार्य नहीं था और इसे अत्यधिक या अनुपातहीन बल का उपयोग नहीं माना जा सकता है।

19. उसने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 103 के प्रावधानों के अनुसार हमलावर को नुकसान पहुंचाना, यहां तक कि मौत की हद तक पहुंचाना उचित है, क्योंकि अपीलार्थी को अपनी संपत्ति के लिए खतरे का सामना करना पड़ा था और इस प्रकार, निचली अदालतने गलत किया है। यह माना गया कि अपीलार्थी ने निजी बचाव के अपने अधिकार से बढ़कर कार्य किया है।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष से 10 गवाह

अर्थात् पीडब्लू-2 मोहन; पीडब्लू-11 भीखा; पीडब्लू-12 रावत सिंह; पीडब्लू-14 नेनु खान; पीडब्लू- 16 धन्ना; पीडब्लू-19 मूलचंद; पीडब्लू- 20 भूरा राम; पीडब्लू-25 गणेशपुरी; पीडब्लू-35 खुशतला सिंह; पीडब्लू-38 जालम सिंह, मुकर गए और अभियोजन पक्ष के तथ्यों से इनकार कर दिया, इसलिए, निचली अदालतको आरोपी-अपीलार्थी को संदेह का लाभ देना चाहिए था।

21. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक, श्री एस. को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जब अपीलार्थी प्रेम सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लोहे का पाइप बरामद किया गया था, जैसाकि प्रदर्श पी-43 से स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने लोहे के पाइप को छिपाने से पहले उसे धोया होगा। इसलिए, पाइप पर खून के धब्बे की अनुपस्थिति शायद ही अभियोजन की कहानी को झुठलाती है।

22. विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि निजी बचाव का अधिकार केवल किसी के व्यक्ति या संपत्ति पर जोखिम को टालने की सीमा तक उपलब्ध है और जैसे ही आसन्न खतरा या आपराधिक कृत्य बंद हो जाता है, ऐसा अधिकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष को लगी कई चोटों को देखते हुए, यह बहुत स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों ने नुकसान पहुंचाने (यदि कोई हो) का खतरा कम होने के बाद भी लंबे समय तक उन पर हमला करना जारी रखा। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया, कि निचली अदालतने यह मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है कि अपीलार्थी ने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, खासकर जब आरोपी पक्ष द्वारा न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई थी और न ही उनकी चोटों का कोई साक्ष्य था।

23. इसके अलावा, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि 48 गवाहों में से 10 गवाह मुकर गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने प्रेम सिंह के अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं किया है। चुनिया (पीडब्लू-1), बड़ी (पीडब्लू-3), कक्कू (पीडब्लू-5), तीजा (पीडब्लू-6), मोती (पीडब्लू-17) और

डॉ. एन.के. के बयानों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है। शर्मा (पीडब्लू-23), कि प्रेम सिंह ने जना के सिर पर लोहे के पाइप/लाठी से प्रहार किया, जिसके अपरिहार्य परिणाम के रूप में, जना की मृत्यु हो गई।

24. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

25. अपीलार्थी के पहले तर्क को ध्यान में रखते हुए, तथ्य यह है कि रोज़नामचा में प्रविष्टि स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि अपीलार्थी ने जाना के सिर पर चोट पहुंचाई, यह निष्कर्ष निकालने का कारण नहीं कहा जा सकता है कि जना को कोई चोट नहीं लगी थी और इस प्रकार, अपीलार्थी की बेगुनाही का साक्ष्य नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता चुनिया ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने देखा कि अपीलार्थी पाइप लेकर आया और मृतक जना को मारा। इसके अलावा चुनिया के माथे पर आरोपी मांग सिंह ने लाठी से वार किया और उसके कंधे पर आरोपी भीख सिंह ने लाठी से वार किया।

26. ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि रोज़नामचा रिपोर्ट में आरोपी व्यक्तियों के प्रत्येक वार से किसने किसे मारा और वास्तव में चोट कहाँ लगी थी। इस न्यायालय की राय है कि निचली अदालतने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता की चोटों का विवरण अनिवार्य रूप से रोज़नामाचा प्रविष्टि में लगाए गए आरोपों के अनुरूप है। इसके अलावा, जब किसी घायल व्यक्ति द्वारा तुरंत रिपोर्ट दी जाती है, तो वह आम तौर पर अपनी चोट के बारे में चिंतित होता है और एक घायल व्यक्ति से सभी व्यक्तियों और उनके संबंधित अपराधियों के बारे में सूक्ष्म विवरण देने की आशा नहीं की जा सकती है।

27. जहां तक अपीलार्थी के दूसरे तर्क का संबंध है कि लोहे के पाइप पर कोई खून के धब्बे नहीं पाए गए हैं, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि खून के धब्बों की अनुपस्थिति इस तथ्य को देखते हुए बहुत कम महत्व रखती है कि लोहे के पाइप पर खून के

धब्बे नहीं पाए गए हैं। अपीलार्थी के आदेश पर बरामद किया गया और सभी गवाहों ने एक सुर में कहा कि अपीलार्थी ने जना के सिर पर चोट पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया था। इसलिए, बिना किसी संदेह के यह सिद्ध हो गया कि बरामद पाइप का इस्तेमाल मृतक जना को घातक चोट पहुंचाने के लिए किया गया था।

28. तीसरा, केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह मुकर गए हैं, अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए 48 गवाहों में से, उन 10 विरोधी गवाहों को छोड़कर सभी ने शिकायतकर्ता के संस्करण का समर्थन किया है।

29. बादी (पीडब्लू-3), एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रेम सिंह एक पाइप लेकर आया और जना के सिर में पाइप से वार किया। इसी तरह, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी कक्कू (पीडब्लू-5) ने भी कहा है कि जब जना बीड़ी पी रहा था, प्रेम सिंह, जिसके हाथ में लोहे का पाइप था, आया और जना के सिर पर पाइप से हमला कर दिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के एक अन्य साथी तीजा (पीडब्लू-6) ने भी इसी तर्ज पर गवाही दी और आगे कहा कि उसके सिर पर चोट लगने के परिणामस्वरूप, जना जमीन पर गिर गया।

30. रिकॉर्ड के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि चश्मदीद गवाह, हीरी (पीडब्लू-7), शांति (पीडब्लू-8), पदा (पीडब्लू-15), मोती (पीडब्लू-17, मृतक की पत्नी), फौदी (पीडब्लू-18), देवी (पीडब्लू-26), गल्बा (पीडब्लू-27) और लच्छी (पीडब्लू-28) लगातार, बार-बार और स्पष्ट रूप से घटनाओं के एक ही संस्करण को दोहराते हैं और पुष्टि करते हैं।

31. जना की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) और चिकित्सा परीक्षक, डॉ. एन के शर्मा (पीडब्लू-23) के बयान से पता चलता है कि जना को निम्नलिखित छह चोटें लगीं:

    1. *दाएं ललाट क्षेत्र के किनारों पर घर्षण के साथ 6.2 x 0.5 सेमी x हड्डी का क्षैतिज कटा हुआ घाव;*

    2. *विरोधाभासी श्वसन के साथ छाती के बाईं ओर का ऊपरी आधा हिस्सा दबा*

हुआ;

3. *दाहिनी आंख की दोनों पलकों के काले पड़ने के साथ हीमेटोमा, दाहिने माथे के क्षेत्र में हेमेटोमा;*

4. *बाएं कान के ऊपरी भाग पर 2.0 X 0.1 X 0.1 सेमी का कटा हुआ घाव;*

5. *बाएं कान के मध्य भाग के पीछे 2.8 X 0.3 X 0.2 सेमी का घाव;*

6. *बाएं पोस्टऑरिक्यूलर क्षेत्र पर गहराई में 2.3 X 0.3 सेमी X मांसपेशियों का स्पिंडल के आकार का कटा हुआ घाव।*

32. मृतक जना के माथे पर लगी चोटें कुंद चोटें थीं, जो लाठी या लोहे के पाइप के जोरदार प्रहार के प्रभाव से हो सकती हैं और प्रकृति के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई चोटों और जना की मृत्यु के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है।

33. इस न्यायालय की राय में, अपीलार्थी द्वारा दी गई दलीलें उसके अपराध को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित संदेह से परे की तो बात ही छोड़ दें।

34. अंत में, यह न्यायालय निजी रक्षा के अधिकार के उचित प्रयोग के संबंध में अपीलार्थी के तर्क पर विचार करता है। निजी सुरक्षा के अधिकार की सीमा को आईपीसी की धारा 99 के तहत स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"धारा 99. .....

जिस सीमा तक अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

-किसी भी मामले में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित नहीं है।

35. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***(2007) 15 एससीसी 241*** में रिपोर्ट किए गए ***धरम और अन्य बनाम हरियाणा सरकार*** के मामले में निजी बचाव के अधिकार की सीमा के बारे में विस्तार से बताया है:

स्पष्ट रूप से कहें तो, निजी रक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है। यह न तो आक्रामकता का अधिकार है और न ही प्रतिशोध का। जहां खतरे की आशंका न हो वहां निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। निजी सुरक्षा का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को उपलब्ध है, जिसे अचानक किसी आसन्न खतरे को टालने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, न कि आत्म-निर्माण की। आवश्यकता वर्तमान, वास्तविक या स्पष्ट होनी चाहिए (देखें: लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य: 1988CriLJ188)।

इस प्रकार, निजी रक्षा के अधिकार के सिद्धांत में अंतर्निहित मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को खतरे का सामना करना पड़ता है और राज्य मशीनरी से तत्काल सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो वह व्यक्ति अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पात्र है। ऐसा होने पर, आवश्यक परिणाम यह है कि नागरिक अपनी या अपनी संपत्ति का बचाव करने के लिए जिस हिंसा का उपयोग करने का पात्र है, वह उस चोट के लिए अनुचित रूप से अनुपातहीन नहीं होनी चाहिए जिसे टाला जाना चाहिए या जिसकी उचित आशंका है और अपने वैध उद्देश्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि एक धमकी भरा व्यक्ति खतरे को टालने और खुद को या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए पल भर में जो साधन और बल अपनाता है, उसे सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता है। अमूर्त मापदंडों को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही विवेकपूर्ण है, जिसे यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है कि धमकी दिए गए व्यक्ति द्वारा अपनाए गए साधन और बल उचित थे या नहीं। इस तरह के प्रश्न का उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि घटनास्थल पर मौजूदा परिस्थितियां, प्रासंगिक समय पर उसकी भावनाएं; भ्रम और उत्तेजना उस पर हमले की प्रकृति आदि पर निर्भर

करती है। फिर भी, निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग कभी भी प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता है। यह निजी रक्षा की अवधारणा के प्रतिकूल होगा।

(बल दिया गया)

36. यह कहना पर्याप्त है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि निजी रक्षा का अधिकार केवल किसी के शरीर या संपत्ति पर जोखिम को टालने के स्तर तक फैला हुआ है और हमलावरों को नुकसान पहुंचाने के क्षेत्र में नहीं जा सकता है। जिस क्षण, जीवन, अंग या संपत्ति के लिए वास्तविक या स्पष्ट खतरा टल जाता है, वह सीमांकन और निर्धारक बिंदु होता है जब कोई कार्य, जो अन्यथा आपराधिक होता है, "रक्षा" के क्षेत्र से अपराध के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है।

37. आईपीसी की धारा 103 के तहत हमलावर की मृत्यु की सीमा तक संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की परिकल्पना की गई है। प्रावधान यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*"**103. जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है** — संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार, धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या गलत करने वाले को कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है, यदि ऐसा अपराध, जिसे करने से, या जिसे करने का प्रयास करने से अधिकार का प्रयोग करने में बाधा आती है, वह इसके बाद गिनाए गए किसी भी प्रकार का अपराध होगा, अर्थात्:-*

प्रथम.— डकैती;

दूसरा.— रात को घर तोड़ना; तीसरा.— किसी इमारत, तंबू या जहाज पर की गई आग से होने वाली क्षति, जिस इमारत, तंबू या जहाज का उपयोग मानव आवास के रूप में, या संपत्ति की हिरासत के लिए जगह के रूप में किया जाता है;

चौथा.- चोरी, शरारत, या घर-अतिचार, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित रूप से यह आशंका हो सकती है कि परिणाम मृत्यु या गंभीर चोट होगी, यदि निजी रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है।

38. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि मृत्यु की सीमा तक संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार केवल चार आकस्मिकताओं के मामले में मौजूद है - डकैती; रात में घर तोड़ना; आग से उत्पात; चोरी, शरारत या गृह-अतिचार जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की आशंका हो।

39. आगामी प्रावधान, धारा 104 में कहा गया है कि चोरी, शरारत या एक अलग प्रकृति के आपराधिक अतिचार के मामले में, निजी बचाव के अधिकार की सीमा केवल हमलावर की मृत्यु के अलावा कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक है।

40. कथित और सिद्ध किए गए तथ्य, रात में घर तोड़ने; आग से उत्पात; या चोरी, शरारत या गृह-अतिचार से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, अपीलार्थी को धारा 103 की सुरक्षात्मक छत्रछाया उपलब्ध नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि आरोपियों के पास जना की मौत का कारण बनने का वैध अधिकार तभी है जब शिकायतकर्ता पक्ष, जिसे हमलावर माना गया है, ने उनके खिलाफ डकैती का अपराध किया या करने का प्रयास किया।

41. आईपीसी की धारा 390 के अनुसार डकैती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

*"**390. डकैती**.— सभी डकैती में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली।*

जब चोरी डकैती है.— ...

***जब जबरन वसूली डकैती है।**—जबरन वसूली "डकैती" है यदि अपराधी, जबरन वसूली करते समय, भय में रखे गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के भय में डालकर जबरन वसूली करता है। चोट पहुंचाना, या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल गलत तरीके से रोकना, और, इस प्रकार भय पैदा करके, उस*

व्यक्ति को उसी समय भय में डाल कर जबरन वसूली गई चीज़ को सौंपने के लिए प्रेरित करता है।"

42. दो अपराधों के मामले में डकैती की जा सकती है। पहले वाले को बढ़ावा देना, अर्थात चोरी, चोरी के अपराध का एक अनिवार्य घटक किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी से संपत्ति छीनने का इरादा है। अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू 33 - काना के बयानों के अनुसार, सरसों की फसल पर अधिकार को लेकर आरोपी पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद था और शिकायतकर्ताओं ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से हस्तक्षेप की भी मांग की थी। घटना के दिन, शिकायतकर्ता इकट्ठा हुए और फसल पर दावा करने/लाने के लिए खेत में गए, जिस पर उनका मानना था कि यह उनका शायद संदिग्ध तरीकों से अधिकार है। इसलिए उनका कृत्य चोरी के दायरे में नहीं आ सकता।

43. डकैती के अंतर्गत दूसरी आकस्मिकता जबरन वसूली की है। प्रस्तुत किए गए और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेम सिंह को शिकायतकर्ताओं द्वारा तत्काल मृत्यु, चोट या गलत तरीके से रोके जाने का डर था। संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी के बयान के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी पक्ष पहले मौखिक विवाद में लगे और फिर, वह मैदान से दूर चला गया और बाद में वापस आया और अपने बचाव में एक पाइप उठाया और उसे चारों ओर घुमाया। जहां तक शिकायतकर्ता पक्ष की भूमिका का प्रश्न है, स्थिति की तात्कालिकता और समग्र तथ्य डकैती का अपराध नहीं बनाते हैं।

44. किसी भी कोण से देखने पर, मृतक जना और उसकी पक्षकार के हमलावर के रूप में पाए गए कार्य आईपीसी की धारा 103 के तहत अपराध की सूची में नहीं आते हैं। इसलिए, अपीलार्थी निजी बचाव के नाम पर हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता है या दूसरे शब्दों में उसका निजी बचाव का अधिकार मौत का कारण बनने तक विस्तारित नहीं है।

45. उपरोक्त निष्कर्ष का एक और कारण है। घटना देवा रावणा राजपूत के खेत में हुई थी

और घटना के समय उक्त भूमि/खेत पर फुटार मल सहित अपीलार्थी का कब्जा तय हो गया था। भले ही यह माना जाए कि शिकायतकर्ता पक्ष अपीलार्थी के खेत से अपने हिस्से की सरसों की फसल जबरन छीनने के लिए लाठियों से लैस होकर आया था, हो सकता है कि वह अपराध करने के इरादे से आया हो, फिर भी यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ताओं ने आपराधिक कृत्य किया होगा। सर्वोत्तम रूप से अतिक्रमण. आपराधिक अतिचार के मामले में संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार आईपीसी की धारा 104 के तहत दिए गए अनुसार मृत्यु का कारण बनने के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने की सीमा तक विस्तारित है।

46. उपरोक्त दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पुष्ट होता है, इसलिए समान तथ्यों वाले मामलों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से भी समर्थित है, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

47. ***(2001) 9 एससीसी 135*** में रिपोर्ट किए ***गए लाटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** के मामले में, एक खेत की जुताई के कारण प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता पक्ष पर "तब्बल" और लाठियों से हमला किया। शिकायतकर्ताओं के ज़मीन पर गिर जाने के बाद भी प्रहार करना जारी रखा। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के कार्यों की वैधता पर इस प्रकार चर्चा की:

> *अब हम विवादित क्षेत्र में हुई घटना को उठाएंगे। इस घटना के संबंध में उच्च न्यायालय, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित क्षेत्र का कब्जा अपीलार्थी के पास था, यह माना गया कि अपीलार्थी को उस संपत्ति की रक्षा करने की सीमा तक निजी बचाव का अधिकार था, जिस पर उसका कब्जा था, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकला कि जहां तक अपीलार्थी और लटेल के बेटे भजन का प्रश्न है, उन्होंने इस अधिकार का उल्लंघन किया है और इस अपराध के लिए आईपीसी की धारा 304, भाग I, के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। अशोक तिवारी की हत्या यहां, हम उच्च न्यायालय के*

निष्कर्ष के साथ एकजुट हैं। इस घटना के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जिन गवाहों के साक्ष्यों की विवेचना की गई है, उनसे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं भजन ने अशोक तिवारी पर तब्बल से हमला किया था, जब वह जमीन पर गिर गये थे। डॉ. चंदेल, पी.डब्लू. 20, जिसने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में साक्ष्य दिया था, ने कहा है कि अशोक तिवारी की मृत्यु सिर की दो चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पार्श्विका और पश्चकपाल हड्डियाँ भी टूट गई थीं और ये चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये 2 चोटें अपीलार्थी और भजन द्वारा निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन करके पहुंचाई गईं।

48. निजी बचाव में हमलावर को होने वाले नुकसान की सीमा के संबंध में आईपीसी की धारा 103 और 104 के बीच परस्पर क्रिया पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ***मंगलदास और अन्य बनाम म.प्र. राज्य*** (1995 की आपराधिक अपील संख्या 337) के मामले में दिनांक 21.09.2011 के निर्णय में चर्चा की जो इस प्रकार है:

वर्तमान मामले में, यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विवादित क्षेत्र 10-15 वर्षों से अपीलार्थीगण के कब्जे में था। यह उन पर कब्ज़ा जमाने में था। अपीलार्थी लंबे समय से दावा कर रहे थे कि विवादित खेत उनकी संपत्ति है और वे मृतक को अपने कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। ये सभी झुलबाई (पीडब्लू-4) के साक्ष्य में स्वीकारोक्ति हैं। झूलबाई (पीडब्लू-4) ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थीगण और उसके पति के बीच उक्त क्षेत्र से संबंधित एक मामला लंबित था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में उनके पति पर विवादित दायर अपास्त से संबंधित फसल काटने के आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक को मृतक भैंस-हल

से खेत जोतने लगा। जब अपीलार्थीगण को इसके बारे में पता चला, तो वे खेत में गए और मृतक को खेत जोतने से मना किया और उसके बाद उन्होंने भैंसों को हल से खोल दिया। इसके बाद, मृतक फिर से भैंसों को खेत में ले आया और उन्हें खेत में बांधने की कोशिश की। हल और खेत जोतने की भी कोशिश की। इस अवसर पर, अपीलार्थीगण ने मृतक पर लाठियों और चतवारों से हमला किया, जो आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। अपीलार्थीगण का विवादित क्षेत्र पर निश्चित कब्ज़ा था, और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार में मृतक पर हमला किया। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण को मृत्यु कारित करने की सीमा तक संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार था या उनका अधिकार मृत्यु के अलावा अन्य हानि कारित करने तक ही सीमित था? इस प्रश्न का उत्तर हमें आईपीसी की धारा 103 और 104 में मिल सकता है। संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार आईपीसी की धारा 103 में उल्लिखित परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने तक फैला हुआ है, जिसमें "आपराधिक अतिक्रमण" शामिल नहीं है जो वास्तव में, मृतक ने वर्तमान मामले में किया है। इसलिए, अपीलार्थीगण के पक्ष में अर्जित अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं हो सकता। वास्तव में, अपीलार्थीगण के पक्ष में अर्जित अधिकार मृत्यु के अलावा किसी भी तरह की हानि पहुंचाने तक विस्तारित होगा जो आईपीसी की धारा 104 से स्पष्ट है जिसमें "आपराधिक अतिचार" का एक उदाहरण शामिल है जो मृतक ने इस मामले में किया था। इसलिए, अपीलार्थीगण ने निश्चित रूप से मृतक की मृत्यु का कारण बनकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।"

49. इस न्यायालय के मद्देनजर, निचली अदालतने सही माना है कि प्रेम सिंह द्वारा मृतक जना को लोहे के पाइप से मारने में बल का अनुपातहीन उपयोग, वह भी उसके सिर पर-शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, यह नहीं कहा जा सकता है निजी बचाव के

अधिकार का एक उचित कार्य हो क्योंकि अपीलार्थी को किसी भी तरह से मौत की तत्काल आशंका नहीं थी - रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य ऐसा नहीं सुझाते हैं।

50. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को निचली अदालतद्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली। वास्तव में, दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 304 भाग । के तहत हो सकती थी या होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि राज्य ने कोई अपील दायर नहीं की है और अपील पिछले 30 वर्षों से लंबित है, इसलिए यह न्यायालय इसे दोषसिद्धि और सज़ा को बदलने के लिए उचित नहीं मानता है।

51. इसलिए, अपील अपास्त कर दी जाती है और आईपीसी की धारा 304 भाग ॥ के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की सजा के संबंध में निचली अदालतके दिनांक 31.07.1990 के आदेश की पुष्टि की जाती है।

52. अपीलार्थी की सजा को पहले से ही भुगती गई सजा तक कम करने की प्रार्थना का विरोध करने के लिए, विद्वान लोक अभियोजक ने दिनांक 09.07.2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी ठहराया गया है और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसे अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर ने अपराध संख्या 173/12.06.2014 में दिनांक 20.02.2020 के आदेश के अनुसार आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत सुनाया है।

53. इसलिए, यह न्यायालय अपीलार्थी को कोई छूट देने के लिए इच्छुक नहीं है। इस प्रकार, निचली अदालतद्वारा दी गई 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000/- के जुर्माने की सजा, और जुर्माना का भुगतान न करने की स्थिति में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा जाता है।

54. प्रकरण क्रमांक 18/1988 में अपीलार्थी प्रेम सिंह को उसकी शेष सजा भुगतनी होगी। चूंकि वह पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इस मामले में उसकी शेष सजा की अवधि इस आदेश की तारीख से शुरू होगी और केस संख्या

173/2014 में दिनांक 20.02.2020 के आदेश द्वारा सुनाई गई उसकी सजा संहिता की धारा 427(2) के आदेश के अनुसार के साथ-साथ जारी रहेगी।

55. वर्तमान आपराधिक अपील तदनुसार निपटाई जाती है।

56. यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो निचली अदालत का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

Inder/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।